मेरा मास्क आपकी रक्षा करता है,

सभी के लिए मास्क
आपका मास्क मेरी रक्षा करता है

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णत: पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 16 DECEMBER TO 22 DECEMBER 2020 • VOLUME- 21 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &

*Pay money after the visa

IELTS | STUDY ABROAD

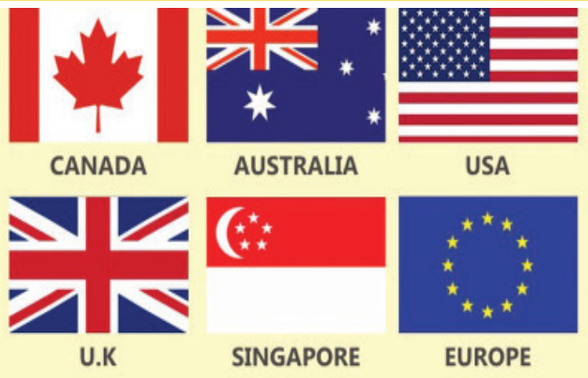

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

*T&C apply

बीजेपी असली टुकड़े-टुकड़े गैंग, पंजाबी हिंदुओं को किसानों के खिलाफ भड़का रही-सुखबीर सिंह बादल

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. मंगलवार को उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी असली टुकड़े-टुकड़े गैंग है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दिया है। बेशर्मी के साथ इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और अब शांतिप्रीय पंजाबी हिंदुओं को सिखों, खास कर किसानों के खिलाफ भड़काने में जुटे हैं।

सुखबीर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बीजेपी पर जमकर हमला करते नज़र आ रहे हैं। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, देश में बीजेपी असली टुकड़े-टुकड़े गैंग है। उसने राष्ट्रीय एकता को तार- तार कर दिया है, बेशर्मी से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया और अब शांतिप्रिय पंजाबी हिंदुओं को सिखों, खास कर किसानों के खिलाफ भड़काने में जुटे हैं। वो लोग देशभक्त पंजाबियों को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल ने एनडीएस से खुद को अलग करने का फैसला किया था। इसके अलावा हरसिमरत कौर बादल ने इन कानूनों की मुखालफत करते हुए केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया था। अकाली दल और बीजेपी का 23 सालो का साथ था, लेकिन किसानों के मुद्दे पर ये साथ टूट गया।

किसानों को किया जा रहा गुमराह, उनकी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार तैयार : पीएम मोदी

■ कच्छ (गुजरात)/ब्यूरो

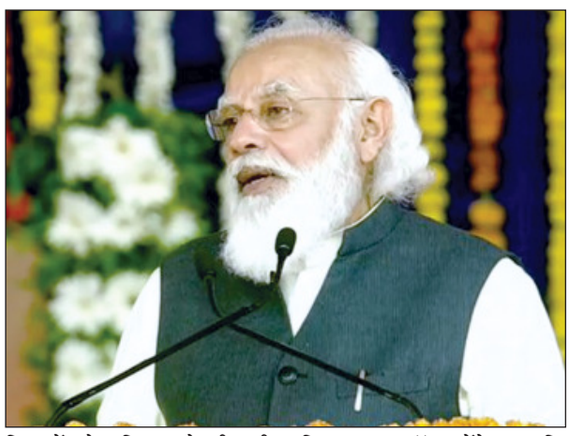

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है और उनकी शंकाओं के समस्याओं के समाधान के लिए चौबीसों घंटे तैयार है। यहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और उन पर किसानों को भ्रमित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा, ''आज कल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग वर्षों से की जा रही थी और अनेक किसान संगठन भी यह मांग करते थे कि किसानों को अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। उन्होंने कहा, ''आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वह भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे। लेकिन अपनी सरकार के रहते वे निर्णय नहीं ले पाए। किसानों को झूठे दिलासे देते रहे।'' मोदी ने कहा कि आज देश ने जब यह ''ऐतिहासिक कदम'' उठा लिया तो विपक्षी किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं।

उन्होंने कहा, ''मैं अपने किसान भाइयों बहनों को बार-बार दोहराता हूं। उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है।

खेती में किसानों का खर्च कम हो, उनकी आय बढ़े और मुश्किलें कम हों, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है।''

उन्होंने हाल के दिनों में आए चुनाव नतीजों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार की ''ईमानदार नीयत'' और ईमानदार प्रयास को करीब-करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई और कहा, ''किसानों के आशीर्वाद की ताकत से... जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूक फोड़ रहे हैं... देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे।

राहुल गांधी ने कसा तंज, बोले- मोदी सरकार के लिए पूंजीपति सबसे अच्छे दोस्त और चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की नजर में आंदोलनकारी किसान 'खालिस्तानी' और पूंजीपति उसके 'सबसे अच्छे दोस्त' हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ''मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं हैं और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी हैं। पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं।'' उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन पिछले करीब तीन सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है।

क्या किसानों को नहीं मिलेगा न्याय? जानें क्या है कोर्ट जाने को लेकर विवाद

केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगभग 20 दिन से जारी है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर जमे हुए हैं। यह किसान लगातार राष्ट्रीय राजधानी के बॉर्डर को सील कर रहे हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। सरकार और किसानों के बीच अब तक लगभग 6 दौर की बातचीत हो चुकी है हालांकि नतीजा अब तक नहीं निकल सका है। एक ओर जहां किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद ही बातचीत को तैयार हैं तो वहीं सरकार इन कानूनों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। इन सबके बीच एमएसपी और कोर्ट जाने को लेकर भी विवाद है। आपको बताते हैं कि आखिर इस कृषि कानून के लागू हो जाने के बाद कोर्ट जाने को लेकर किसानों के मन में किस तरीके का डर है।

इस कृषि कानून में एक ऐसी धारा जुड़ी है जो किसी भी परिस्थिति में किसानों के कोर्ट जाने के अधिकार को खत्म कर रही है। यह धारा है कृषक उपज ट्रेड और कॉमर्स कानून। जानकारों की माने तो वह भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस धारा के तहत जो प्रावधान किए गए हैं वह संविधान के तहत मान्य नहीं है। उनका दावा है कि इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी और नौकरशाही के सामने उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकेगा। इस कानून की धारा 13 और धारा 15 को लेकर किसानों के मन में संशय है। धारा 13 यह कहता है कि केंद्र सरकार या उसके अधिकारी, राज्य सरकार या उसके अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो पाएगी। धारा 15 की बात करें तो किसी भी सिविल कोर्ट का इस कानून में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। यह मामला तहत जिस अथॉरिटी को अधिकृत किया गया है, सुनवाई हर हाल में वही होगी। लगातार इन्हीं धाराओं को रद्द करने की मांग किसान कर रहे हैं।

उनका आरोप है कि इससे उनके कानूनी हक को छीना जा रहा है। हालांकि एसडीएम और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दाखिल की जा सकेगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था के तहत किसानों को त्वरित, सुलभ और कम लागत पर न्याय मिल सकेगा। इन कानूनों में यह भी कहा गया है कि किसी भी विवाद की स्थिति में उसके समाधान स्थानीय स्तर पर 30 दिनों के भीतर हो सकेगा। पहली व्यवस्था इसमें सुहल बोर्ड के माध्यम से आपसी समझौते की है।

किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। सरकार और किसानों के बीच अब तक लगभग 6 दौर की बातचीत हो चुकी है हालांकि नतीजा अब तक नहीं निकल सका है।

अब क्यों नहीं सुनने को मिलते पंजाब पुलिसकर्मियों की तरफ से श्रीमान और श्रीमती जैसे शब्द

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

पिछले कुछ दिनों से पंजाब पुलिस के कर्मियों को जालंधर में विवादों का सामना करना पड़ रहा है कुछ दिन पहले उनका पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था। ऐसा ही कुछ मामला बाद में पुलिस कर्मियों और वकीलों के बीच कोर्ट परिसर में विवाद देखने को मिला और अब एक दो दिन पहले सत्ताधारी पार्टी के पार्षद के साथ रास्ता न देने के कारण नौबत धरने तक आ गई लेकिन हर बार विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा उन कर्मियों के ऊपर विभागीय कार्रवाई करके हर एक मामले को शांत किया गया। पुलिस विभाग जिस पर लोग इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे होते है अगर उनके कर्मचारी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठने लगेगा जैसे कुछ सालों पहले श्रीमान जी और श्रीमती जैसे शब्द पुलिसकर्मियों की तरफ से लोगों को सुनने को मिलते थे चाहे वह पुलिस स्टेशन जाए या सड़क पर चैकिंग के लिए पुलिसकर्मी द्वारा रोका जाए उन शब्दों की अब लोगों को कमी महसूस हो रही है।

तभी पुलिस विभाग और आम लोगों के बीच आपस में तालमेल बढ़ सकता है और अधिकारियों को भी कही विवाद होने पर सड़क जाम और धरने जैसी स्थिति में नहीं पड़ना पड़ेगा

पिछले कुछ सालों से आपको देखने को मिला होगा की पंजाब सरकार द्वारा काफी पुलिस कर्मियों को प्रमोट करके उच्च पदवी दी गई है। क्या विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों को साल में दो बार अच्छे से ट्रेनिंग देकर बोलने के स्कील्स और फिजिकल फिटनेस जैसे टेस्ट रख कर उनकी काबलियत के तहत उन्हें तैनात नहीं किया जाना चाहिए? तभी पुलिस विभाग और आम लोगों के बीच आपस में तालमेल बढ़ सकता है और अधिकारियों को भी कहीं विवाद होने पर सड़क जाम और धरने जैसी स्थिति में नहीं पड़ना पड़ेगा क्यूंकि जब तक लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास नहीं बढ़ेगा तब तक विवादों के मामले आये दिन आपको सुनने में मिलते रहेंगे।

कृषि आंदोलन: किसान नेताओं की चेतावनी, बुधवार को पूरी तरह बंद करेंगे चिल्ला बॉर्डर

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

केन्द्र सरकार की तरफ से लाए गए तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली-नोएडा सड़क वाले चिल्ली बॉर्डर को बुधवार को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी है. सिंघु बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि लड़ाई ऐसे दौर में पहुंच गई है, जहां पर हम जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेता इंद्रजीत दीघे ने कहा कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लोग 20 दिसंबर को गांवों, प्रखंडों में श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को देश के 350 जिलों में हमारा प्रदर्शन सफल रहा, किसानों ने 150 टोल प्लाजा को 'मुक्त' कराया।

किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम इस आंदोलन को और विशाल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक कैंपेन की शुरुआत कर रही है कृषि बिलों को प्रमोट करने के लिए. इन्द्रजीत ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक आंदोलन है और किसानों की एकता को तोड़ने की हर संभव कोशिश विफल होगी। इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि कल 150 टोल प्लाजा फ्री हुए, 350 गांव में आंदोलन हुआ. उससे सरकार बौखला गई है। अब उन्होंने फुट डालने के लिए एसवाईएल का मुद्दा उठा दिया है। 21 दिन में पानी मांग रहे हैं, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इसकी एकता नहीं तोड़ी जा सकती। ये कामयाब नहीं होने वाला। पहले से योजना बनाकर कॉरपोरेट्स ने कानून बनवाये। इधर, युद्धवीर सिंह ने कहा कि देश के किसान उनकी शहादत को बेकार नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया हैरान करने वाला है। युद्धवीर ने कहा कि पीएम एक तरफ कह रहे हैं कि वे किसानों के साथ हैं और दूसरी तरफ फिक्की की सभा में कॉर्पोरेट्स को कह रहे हैं कि वे कृषि क्षेत्र में आएं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जिद पर है। सरकार ये गलतफहमी निकाल दें कि इनकी संख्या घटेगी। सरकार ये जान लें कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।

दखल

अर्थव्यवस्था में भरोसे का संकट

भारत की जीडीपी में उपभोक्ता खर्च की हिस्सेदारी साठ फीसद से अधिक है। जबकि रोजगार की दर गिर कर 36.2 फीसद हो गई है, यानी श्रमशक्ति का 63.8 फीसद हिस्सा बेरोजगार है। जिनके पास रोजगार है, उनकी भी कमाई घट गई है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को मजबूत कर भरोसे वाली अर्थव्यवस्था का भरोसेमंद मॉडल विकसित करना होगा, ताकि भरोसा हमेशा बना रहे और अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे।

भरोसा एक ऐसा शब्द है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी पर दुनिया टिकी है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब भरोसे पर टिका है। भरोसा है तो व्यवस्था चलती है, भरोसा उठ गया तो सब ठप हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी यह उपयुक्त लगता है। भरोसा डगमगाते ही अर्थ की व्यवस्था डगमगाने लगती है। इसलिए अर्थ और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि लोगों का इस पर भरोसा बना रहे। कोरोना विषाणु के प्रकोप बाद अर्थव्यवस्था लुढ़क कर गहरी खाई में चली गई। पहली तिमाही में देश की जीडीपी दर इतिहास में पहली बार शून्य से नीचे 23.9 फीसद पर पहुंच गई। दूसरी तिमाही में इसमें सुधार जरूर हुआ, लेकिन अभी भी यह शून्य से नीचे साढ़े फीसद पर है। इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि अर्थव्यवस्था औपचारिक रूप से मंदी में जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का हालांकि कहना है कि सुधार की मौजूदा रफ्तार बनी रही तो तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल आएगी। लेकिन इस रफ्तार के बने रहने के संकेत फिलहाल नहीं हैं।

कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तीसरी तिमाही में जीडीपी और नीचे जा सकती है, क्योंकि दूसरी तिमाही का सुधार त्योहारी मौसम में मांग बढ़ने के कारण हुआ है, जिसके तीसरी तिमाही में बने रहने की संभावना नहीं है। उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था पर भरोसा कोरोना से पहले ही डगमगाने लगा था। वित्त वर्ष 2018-19 में 6.1 फीसद की वृद्धि दर 2019-20 में 4.2 फीसद पर आ गई। लेकिन कोरोना के बाद भरोसा उठ-सा गया। आरबीआई के उपभोक्ता भरोसा सर्वेक्षण के अनुसार, सितंबर में अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआइ) रिकार्ड निचले स्तर 49.9 पर चला गया। इसके पहले जुलाई में यह 53.8 पर और मई में 63.7 पर था। पिछले दस सालों के दौरान 2010 की चौथी तिमाही में उपभोक्ताओं का भरोसा 116.70 के सर्वोच्च स्तर पर था। उस दौरान (2010-11 की चौथी तिमाही में) जीडीपी वृद्धि दर 9.2 फीसद थी। हालांकि अगले साल यानी 2021 को लेकर उपभोक्ता आशावान हैं, क्योंकि अगस्त-सितंबर के सर्वेक्षण में भविष्य उम्मीद सूचकांक (एफईआइ) 115.9 पर था, जो जुलाई में 105.4 और मई में 100 से नीचे चला गया था। इस सूचकांक के 100 से नीचे जाने का अर्थ होता है कि भविष्य की स्थिति वर्तमान से भी खराब हो सकती है।

शायद सितंबर के एफईआइ के आधार पर ही कहा जा रहा है कि अगली तिमाही में या अगले साल अर्थव्यवस्था मंदी से उबर जाएगी। लेकिन यह सिर्फ उम्मीद है, और जब तक यह भरोसे में नहीं बदल जाती, सुधार का जश्न बेमानी है। सवाल उठता है कि उपभोक्ताओं की उम्मीद भरोसे में कैसे बदलेगी? उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था पर भरोसा तब बढ़ता है, जब उन्हें आमदनी का भरोसा हो जाए, यानी उनके पास रोजगार हो, नौकरियां हों। सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि श्रम बाजार में रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है और रोजगार दर 2016-17 (42.8 फीसद) से ही लगातार नीचे जा रही है। पिछले महीने यानी नवंबर के प्रथम सप्ताह में 37.5 फीसद, दूसरे सप्ताह में 37.4 फीसद और 22 नवंबर को समाप्त तीसरे सप्ताह में रोजगार दर लुढ़क कर 36.2 फीसद पर चली गई। अब तीसरी तिमाही के दो महीने बीत चुके हैं और रोजगार दर की यह हालत है। ऐसे में उपभोक्ताओं की उम्मीद को भरोसे में बदलने की उम्मीद कैसे की जाए?

तीसरी तिमाही में तो संभावना न के बराबर है। रोजगार दर नीचे होने का मतलब है उपभोक्ताओं के पास आमदनी नहीं है। आमदनी न होने पर जाहिर-सी बात है वे खरीदारी नहीं करेंगे और बाजार में मांग नहीं होगी। फिर उत्पादन नहीं होगा और उत्पादन नहीं होगा तो नौकरियां पैदा नहीं होंगी। यह स्थिति अधिक अवधि तक बनी रहती है तो जीडीपी का आकार घटने लगता है और महंगाई भी बढ़ जाती है। पिछले वित्त वर्ष (2019-20) में भारत की जीडीपी 2.94 खरब डॉलर थी और देश दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अब 2020 में भारत की जीडीपी का आकार घट कर 2.6 खरब डॉलर होने की बात कही जा रही है और देश अब एक पायदान नीचे खिसक कर दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था होगा। उत्पादन कम होने और मांग अधिक होने से महंगाई बढ़ती है। लेकिन इस समय मांग न होने के बावजूद महंगाई बढ़ रही है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर छह साल के उच्चस्तर 7.61 फीसद पर पहुंच गई।

सबसे बड़ा आश्चर्य खाद्य महंगाई दर को लेकर है, जो अक्टूबर में बढ़ कर 11.07 फीसद हो गई। जबकि कृषि विकास दर दूसरी तिमाही में भी 3.4 फीसद पर बनी हुई है और सरकार के अनुसार अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थव्यवस्था की इस स्थिति को मुद्रास्फीतिजनित मंदी कहते हैं। तो भारत सिर्फ मंदी ही नहीं, बल्कि मुद्रास्फीति जनित मंदी की चपेट में है। इस मंदी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भरोसा ही है। लेकिन सवाल उठता है कि उपभोक्ताओं में यह भरोसा जागेगा कैसे और इसे कौन जगाएगा? भारत की जीडीपी में उपभोक्ता खर्च की हिस्सेदारी साठ फीसद से अधिक है। जबकि रोजगार की दर गिर कर 36.2 फीसद हो गई है, यानी श्रमशक्ति का 63.8 फीसद हिस्सा बेरोजगार है। जिनके पास रोजगार है, उनकी भी कमाई घट गई है।

परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं का भरोसा रिकार्ड निचले स्तर 49.9 पर चला गया है। इस भरोसे को ऊपर उठाने के सिवाय अर्थव्यवस्था को उबारने का दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में हमें यह देखना होगा कि कहां क्या किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने उपाय किए भी हैं। लेकिन अब तक किए गए उपाय अपेक्षित परिणाम देते नजर नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर उपाय निजी क्षेत्र के उद्यमों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाले रहे हैं। जबकि निजी क्षेत्र सिर्फ बाजार में मांग बढ़ने से प्रोत्साहित होता है। हां, जहां सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सीधे तौर पर उपाय किए हैं, वहां परिणाम दिखा है। मनरेगा के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों के भत्तों में भले कटौती हुई हो, लेकिन नौकरियां नहीं गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र ने कोरोना काल में शानदार काम किया है। कमजोर ढांचे के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य महकमे ने ही कोरोना से लोहा लिया। कृषि क्षेत्र ने इस संकट में सुरक्षा कवच का काम किया है। अर्थव्यवस्था के खाई में लुढ़क जाने के बावजूद कृषि क्षेत्र में लगातार दो तिमाही से 3.4 फीसद की वृद्धि दर बनी हुई है।

जब देश पर संकट आता है तो यही निजी क्षेत्र मददगार बनने के बदले अपने दरवाजे बंद कर घर के अंदर बैठ जाता है। यह अलग बात है कि निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तात्कालिक वृद्धि दर मुहैया कराता है, लेकिन अर्थव्यवस्था चक्र में थोड़ा-सा व्यवधान आने पर अर्थव्यवस्था को उसी रफ्तार से नीचे भी पहुंचा देता है। भरोसेमंद उसी को माना जाता है, जो संकट में साथ दे। लिहाजा हमें सार्वजनिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को मजबूत कर भरोसे वाली अर्थव्यवस्था का एक भरोसेमंद मॉडल विकसित करना होगा, ताकि उपभोक्ताओं का भरोसा हमेशा बना रहे और अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे।

विचार

एमएसपी बना गले की फांस

किसान आंदोलन के दौरान भारत बंद के बाद अब नजर समाधान पर टिकी है। सरकार कानून में बदलाव को तैयार है, तो किसान चाहते हैं कानून को रद्द किया जाए। मामला अब प्रतिष्ठा से जुड़ चुका है तो दोनों ही पक्षों को बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा।

तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए चल रहे किसान आंदोलन ने भारत बंद भी करा लिया। बावजूद इसके समाधान के आसार नहीं दिख रहे हैं। 9 दिसंबर को एक बार फिर सरकार से वार्ता का दौर तय है, यह मुकाम पर पहुंचेगा या नहीं, कहना कठिन है। दरअसल, आंदोलन में मुख्य पेंच न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी को लेकर बना हुआ है। एमएसपी के सवाल पर आंदोलनकारी किसान संगठन ही नहीं बल्कि संघ के अनुषांगिक संगठन भी सरकार के खिलाफ हैं। हालांकि इस मांग से जुड़ी जटिलताओं के कारण सरकार पूरी तरह असमंजस में है। अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी की घोषणा कर दी जाए तो तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग संबंधी स्वर धीमे हो सकते हैं क्योंकि सरकार पहले से ही इन कानूनों के कई प्रावधानों में संशोधन के लिए तैयार है। सरकार किसानों को सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने, एनएसआर क्षेत्र से जुड़े नए प्रदूषण कानून में बदलाव करने, निजी खरीददारों के लिए पंजीयन अनिवार्य करने और छोटे किसानों की हितों की रक्षा के प्रावधानों में बदलाव को तैयार है।

पांचवें दौर की बैठक के बेनतीजा रहने के बाद सरकार में आंदोलन खत्म कराने के लिए माथापच्ची जारी है। मुख्य चिंता एमएसपी को लेकर है। कृषि मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच शनिवार रात से ही कई दौर की बातचीत हुई है। इस पर अंतिम निर्णय से पहले सरकार किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के जरिए उनका दमखम भी देख चुकी है। आजादी के बाद से ही सरकारें किसान और ग्राहकों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने में नाकाम रही हैं। इसके कारण ग्राहकों को तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी, मगर ग्राहक के द्वारा चुकाई गई रकम का मामूली हिस्सा ही किसानों की जेब तक पहुंचा। मसलन ग्राहकों ने कई बार किसान द्वारा बेची गई रकम से चार से पांच गुना अधिक कीमत चुकाई। कृषि क्षेत्र का मुनाफा बिचौलियों की भेंट चढ़ता रहा। आजादी के सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकारें किसानों का आय बढ़ाने में नाकाम रही। केंद्र सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की है। एमएसपी को सरकार कानूनी तो बना देगी, मगर निजी क्षेत्र को खरीदारी के लिए बाध्य नहीं कर पाएगी। ऐसे में अगर फसल की मांग कम हुई तो निजी क्षेत्र खरीदारी करेंगे ही नहीं।

सरकार एक सीमा तक ही एमएसपी के तहत खरीदारी कर सकती है। सरकार औसतन कुल उपज का छह फीसदी की ही खरीद करती है। वर्तमान क्षमता के अनुरूप इसे दस फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। भंडारण क्षमता, अर्थव्यवस्था पर बोझ सहित कई ऐसे कारण है जिसके चलते सरकार अधिक मात्रा में अनाज नहीं खरीद सकती। किसी एक फसल की अधिक उपज होने के बाद उसकी मांग में कमी आएगी। सरकार एक सीमा से अधिक फसल नहीं खरीदेगी। सरकार हर मांग मानने को तैयार है, किसान भी जिद छोड़ें।

बचाना होगा छोटी नदियों को

छोटी नदियों पर संकट का निदान उसके संरक्षण में है। नदियों का संकट में होना संकट का कारण बन सकता है। 1951 में प्रति व्यक्ति चौदह हजार लीटर पानी सहजता से उपलब्ध था। लेकिन अनुमान है कि 2050 तक पानी की उपलब्धता तीन हजार लीटर प्रतिव्यक्ति ही रह जाएगी। यह स्थिति डराती है। ऐसे में समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम नदियों के प्रति संवेदनशील हों, अन्यथा आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे।

आमतौर पर गर्मी ऋतु में देश के कई हिस्सों से इस आशय की खबरें आती हैं कि छोटी नदियां सूख गईं या कुछ बड़ी नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई। लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में बहने वाली उजाड़ नदी इस वर्ष नवंबर महीने में ही सूख गई। उजाड़ चंबल की सहायक नदी है और अंचल के बहुत सारे गांवों के लिए जीवनरेखा है। आमतौर पर उजाड़ नदी में इतना पानी रहता था कि उससे जुड़े गांवों में आवागमन सुनिश्चित करने के लिए 55 मीटर लंबा पुल बनाया गया है। लेकिन अपने जल से इलाके को विकास का वरदान सौंपने वाली यह नदी समाज की अपने प्रति असंवेदनशीलता के कारण अब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए छटपटाती-सी प्रतीत होती है।

दरअसल, अपने प्रति संवेदनहीनता का दंश झेल रही उजाड़ नदी देश की अकेली नदी नहीं है। देश में ऐसी सैकड़ों सहायक नदियां होंगी जो इस तरह असमय सूख कर दम तोड़ रही हैं और मनुष्य के लिए जल संकट के खतरे की घंटी बजा रही हैं। लेकिन लगता है हम इस खतरे को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गंगा को तो हमारी मान्यताओं में बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को अंतिम समय यदि गंगाजल की दो बूंदों का भी आचमन मिल जाए तो सांसारिक बंधनों से उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन देवी माने जाने वाली गंगा नदी स्वयं अब प्रदूषण के दुर्दांत प्रतीत होते असुर से संघर्ष करने पर विवश है। पिछले दिनों यमुना में प्रदूषण के कारण उठे झागों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चलीं। सदा सलिला कही जाने वाली चंबल नदी के पानी को भी परीक्षण में कई स्थानों पर पीने योग्य नहीं पाया गया है।

कावेरी नदी 40 प्रतिशत से अधिक अपना जलप्रवाह खो चुकी है, तो कृष्णा और गोदावरी नदी में पानी की मात्रा दो दशक पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। जब देश की महनीय नदियों का यह हाल है तो छोटी नदियों और बरसाती नदियों की स्थिति का अनुमान तो आसानी से लगाया जा सकता है। यह स्थिति इसलिए चिंता पैदा करती है क्योंकि हमारी पानी की जरूरत का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नदियां ही पूरा करती हैं। पानी केवल पीने या रोमजर्रा की जरूरतों को पूरा करने या सिंचाई के काम ही नहीं आता, अपितु औद्योगिक उत्पादन में कच्चे माल के परिशोधन सहित अनेक क्रियाओं में पानी ही जरूरी होता है। ऐसे में जिन देशों को प्रकृति ने नदियों का वरदान दिया है, उन्हें नदियों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत थी।

लेकिन दुर्भाग्य से विकास की आपाधापी ने नदियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को छीन लिया। हमने नदियों को बचाने और संरक्षित रखने के बजाय के उनके प्रवाह क्षेत्र में ही बस्तियां बनानी शुरू दीं।

यह तो समझ आता है कि नदियों के प्रवाह पर बांध बनाना जीवन की जरूरत था, लेकिन नदियों के किनारों पर अतिक्रमण कर लेना या उनमें मनमाने तरीके से गंदगी प्रवाहित करना कैसे उचित कहा जा सकता है? स्थिति यह हो गई कि हम नदियों को देवी मान कर पूजते तो रहे, लेकिन उनकी पवित्रता से खिलवाड़ भी करते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नदियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भारत में ही हुआ। अपने सीमित संसाधनों से आकाश की अथाह ऊंचाई नापने की आपाधापी में कई विकासशील देशों ने नदियों की महत्ता को नजरअंदाज किया है। ब्राजील के रियो-दे जेनेरियो की सारापुई या सुपुई नदी कचरे से इस कदर भर गई है कि उस पर पैदल चला जा सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सभी 16 प्रखंडों से कोई न कोई नदी गुजरती है। लेकिन इन नदियों में से अधिकांश अपनी दुर्दशा पर आंखें बहा रहीं हैं। नदियों की अत्यधिक संख्या के कारण मिथिला को तो नदियों का मायका तक कह दिया जाता है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि नदियां अपने मायके में ही दुख के साथ बह रही हैं। बिहार की बूढ़ी गंडक, लखनदेई, टिमदा, झझा, सियारी, कदाने, बाया, डंडा, मनुषमारा जैसी नदियां या तो दम तोड़ चुकी हैं या दम तोड़ने के कगार पर हैं।

झारखंड में पिछली गर्मियों में 133 नदियों के सूखने की खबरें आई थीं। पलामू जिले की ही कोयल, सदाबह, अमानत नदियां अस्तित्व के लिए जूझती दिखीं। गुमला जिले में नदी के प्रवाह क्षेत्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखे। किसी नदी के सिकुड़ने या सूखने का दर्द क्या होता है, यह उन इलाकों में जाकर जानना चाहिए जिन इलाकों ने इस स्थिति का सामना किया है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से बेहतर किसी नदी के महत्त्व को कहां समझा जा सकता है? कहते हैं कि पौराणिक नदी सरस्वती का प्रवाह इसी क्षेत्र में था। शोधकर्ताओं के अनुसार करीब 150 पहले भी राजस्थान के इस इलाके के प्रमुख शहर बीकानेर के पास नाल गांव में एक नदी बहती थी, लेकिन धीरे-धीरे वह लुप्त हो गई। जर्मनी के द मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस आफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय और कोलकाता के भारतीय विज्ञान शिक्षा और शोध संस्थान (आइआइएसईआर) जैसे संस्थानों से जुड़े विद्वानों ने यह शोध किया था। इससे कुछ ही दूर स्थित सीकर जिले की साइवार की पहाड़ियों से निकलने वाली साहबी नदी की तो सौ से अधिक उपनदियां थीं। इस नदी के प्रवाह का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर मासनी बांध बनाया गया। लेकिन यह नदी भी अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

कुछ विद्वानों ने पौराणिक दृष्दावती नदी के रूप में इसे पहचाना है। सोता, कृष्णावती, दोहन आदि इस नदी की उपनदियां थीं। एक नदी के रूठने के डर से दन दिनों दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे भी गुजर रहा है। यहां की राजधानी असुनशियोन के पास से गुजरने वाली नदी पराग्वे ही इस देश को समुद्र से जोड़ने वाला एकमात्र विकल्प थी। इस देश के लिए पराग्वे नदी के महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी नदी के नाम पर देश का नाम भी रखा गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी-नासा द्वारा पिछले दिनों जारी एक तस्वीर में यह दिखाया गया है कि कैसे राजधानी असुनशियोन के आसपास नदी का इलाका सूख गया है। पराग्वे के लोक निर्माण विभाग के निदेशक जॉर्ज वेगार्ग ने पिछले दिनों कहा भी कि 'नदी सूखने का असर सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि पराग्वे का 52 फीसद आयात और लगभग 75 प्रतिशत निर्यात नदी के रास्ते से ही होता है।' नदी के सूखने ने दूरस्थ इलाकों की बस्तियों में पेयजल आपूर्ति को भी प्रभावित किया है।

नदियां मानव सभ्यता की उन्नायक रही हैं। प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी नदी घाटी में हुआ है। लेकिन अब नदियां संकट में हैं। नदियों का संकट में होना आमजन के लिए भी संकट का कारण बन सकता है। सन 1951 में हमारे यहां प्रतिव्यक्ति चौदह हजार 180 पानी सहजता से उपलब्ध था। लेकिन अनुमान है कि सन 2050 तक पानी की उपलब्धता तीन हजार एक सौ बीस लीटर प्रतिव्यक्ति ही रह जाएगी। यह स्थिति डराती है। देश में जहां छोटी नदियों के प्रवाह क्षेत्र अतिक्रमण के शिकार हो गए हैं, वहीं 265 मझोली नदियां संकट में हैं। बड़ी नदियां भी प्रदूषण का शिकार हो रही हैं।

ट्विटर

सरकार किसान कानूनों को रद्द करे और आंदोलन को खत्म कराए। आज देश की जो हालत है, वह सरकार की हठधर्मिता का परिणाम है। सरकार जिद छोड़े।

सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष

विपक्ष किसानों का सहारा लेकर सरकार को बदनाम करना चाह रहा है। विपक्ष को अगर किसानों की चिंता होती तो इस तरह के बदलाव पहले ही हो जाते।

रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री

सत्यार्थ

गरीबों की सेवा ही तीर्थयात्रा

अपनी हज यात्रा पूर्ण कर एक दिन अब्दुला बिन मुबारक काबा में ही सोए हुए थे। तभी उन्होंने सपने में दो फरिश्तों को आपस में बातें करते हुए देखा। एक फरिश्ते ने पूछा -इस साल हज के लिए कितने लोग आए और उनमें से कितनों की दुआ कबूल हुई? दूसरे फरिश्ते ने कहा- वैसे तो हज करने को लाखों लोग आए थे, मगर इनमें से दुआ किसी की भी कबूल नहीं हुई। इस वर्ष दुआ सिर्फ एक की ही कबूल हुई है और वह भी ऐसे इंसान की है, जो यहां आया भी नहीं था। यह सुनकर पहले फरिश्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस ने हैरानी से पूछा-भला वह कौन ऐसा खुशनसीब है, जो कि यहां आया भी नहीं और उसकी दुआ भी कबूल हो गई? तब दूसरा फरिश्ता बोला- वह है दमिश्क का मोची अली बिन मूफिक। फरिश्तों की ये बातें सुनकर अब्दुला ने सोचा कि उस पाक हस्ती से जरूर मिलना चाहिए। मोची से मिलने को अब्दुला अगले ही दिन दमिश्क के लिए चल पड़े और वहां उनका घर भी ढूंढ लिया।

अब्दुला बिन मुबारक ने मोची से पूछा-क्या तुम हज को गए थे? इतना सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। न में सिर हिलाते हुए कहा- मेरा मुकद्दर कहां, जो हज को जा पाता! जिंदगी भर की मेहनत से कुछ दिरहम हज के लिए जमा किए थे, मगर एक दिन देखा कि पड़ौस में गरीब लोग पेट की आग बुझाने के लिए वे चीजें खा रहे हैं, जिन्हें खाया ही नहीं जा सकता। उनकी बेबसी ने मेरा दिल हिला दिया और हज के लिए जो रकम जमा की थी, उन गरीबों में बांट दी। अब हज पर जाऊंगा भी तो कैसे। कोई सूरत नजर नहीं आती। इस तरह अब्दुला बिन मुबारक समझ गए कि उस शख्स को हज पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीन-दुखियों की मदद ही सच्ची तीर्थयात्रा है।

मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन

नई दिल्ली में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को गाजीपुर सीमा पर एक सिख युवक ने अपने गतका मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन किया।

डोनाल्ड ट्रंप के रुख से अमेरिका में बढ़ा संकट

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को इलेक्टोरल कॉलेज में मतदान से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों ने देश में राजनीतिक संकट बढ़ा दिया है। दो रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में टेक्सास राज्य की याचिका खारिज होने के बाद ट्रंप खेमे के पास मौजूद कानूनी विकल्प लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के बजाय ट्रंप और उनके समर्थकों ने नए मोर्चे खोल दिए हैं।

सोमवार तड़के डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में सीधे सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है कि वह विभिन्न राज्यों के बीच के मसलों पर फैसला दे, किंतु सुप्रीम कोर्ट का इसके बीच न आना बेतुका है। उन्होंने गुण-दोष के आधार पर इस मामले में फैसला नहीं दिया। हमारा देश इतना बुरा हो गया है। टेक्सास समेत चार राज्यों में हुए मतदान की वैधता को चुनौती दी थी। इन राज्यों से डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उसके बाद कई शहरों में ट्रंप समर्थक सड़कों पर उतर आए। रविवार को वॉशिंगटन में ट्रंप समर्थक धुर दक्षिणपंथी गुट प्राउड बॉयज और ट्रंप विरोधी एटिंफा गुट के बीच हिंसा हुई। चार लोगों पर हमला हुआ, जिन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया।

रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने की सेना से हस्तक्षेप की मांग

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने सीधे सेना से हस्तक्षेप करने और देश के विभाजन की मांग की है। रिपब्लिकन पार्टी के टेक्सास राज्य के अध्यक्ष एलन वेस्ट ने कहा कि कानून- व्यवस्था में यकीन करने वाले राज्यों को अब संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि (सुप्रीम कोर्ट का) ये फैसला एक ऐसी मिसाल कायम करता है, जिसका मतलब है कि राज्य अमेरिकी संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं, जबकि उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए अब शायद समय आ गया है, जब कानून का पालन करने वाले राज्य एकजुट होकर एक ऐसे संघ का निर्माण करें, जो संविधान का पालन करे।

1860 के दशक के बाद नहीं उठी राज्यों के अलगाव की बात

विश्लेषकों ने ध्यान दिलाया है कि अमेरिका में 1860 के दशक के बाद राज्यों के अलगाव की बात कभी किसी ने नहीं की। 1860 के दशक में जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गुलामी प्रथा खत्म करने का फैसला किया था, तब अमेरिका के दक्षिण राज्यों उसके खिलाफ बगावत कर स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया था। इसको लेकर ही गृह युद्ध हुआ, जिसमें राज्यों की बगावत को कुचलते हुए देश की एकता की रक्षा की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई : मैकेनी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप के वकील रूडी जुइलियानी ने टीवी चैनल फॉक्स के एक कार्यक्रम में कहा कि ये फैसला इसलिए आया, क्योंकि तथ्यों को दबाया गया है। इसी चैनल पर व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी किलेह मैकेनी ने सुप्रीम कोर्ट की यह कहकर कड़ी आलोचना की कि उसने प्रक्रियाओं की आड़ लेकर इस मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

न्यूज

योगी ने शहीद डिप्टी कमाण्डेंट को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

लखनऊ, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में कर्तव्य पालन के दौरान मुजफ्फरनगर निवासी सीआरपीएफ के शहीद डिप्टी कमाण्डेंट विकास कुमार के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद विकास कुमार के नाम पर करने की भी घोषणा की है। श्री योगी ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ है।

रामलला को ठंड से बचाने किए गए तमाम उपाय

अयोध्या, (एजेंसी)। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर विराजमान भगवान रामलला को ठंड से बचाने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं। श्रीरामजन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने बताया कि भगवान रामलला बालरूप में विराजमान हैं और ठंड से उनको बचाने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं। रामलला के दरबार में ब्लोअर लगाया गया है। भगवान को ऊनी वस्त्र, रजाई व कंबल ओढ़ाया जा रहा है तो कहीं गर्भगृह में ब्लोअर के जरिए भगवान को ठंड से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भगवान के भोग, श्रृंगार, आरती में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट की याचिका खारिज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के एक न्यायिक अधिकारी की वह याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री पर गैर पेशेवराना तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया था। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी रमासुब्रमण्यन की पीठ ने न्यायिक मजिस्ट्रेट सैयदुल्ला खलीलुल्लाह खान की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की गैर पेशेवर गतिविधियों पर सवाल खड़ा करते हुए आम लोगों के साथ केसों को सूचीबद्ध करने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया था।

आतंकवाद प्रायोजकों की सूची से सूडान का नाम बाहर

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका ने सूडान का नाम 'आतंकवाद प्रायोजक देशों' की सूची से बाहर कर दिया है तथा यह निर्णय सोमवार से लागू हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रविवार को इस आशय की अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए। दूतावास ने इस कदम के बारे में जानकारी साझा करते हुए अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि 45 दिनों की कांग्रेस की अधिसूचना अवधि समाप्त हो गई है और विदेश मंत्री (पोम्पियो) ने सूडान को आतंकवाद प्रायोजक की सूची से बाहर रखने के लिए एक अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए हैं जो सोमवार से प्रभावी है।

मुंबई महानगरपालिका की तरफ से पानी के बिल के बकायेदारों की एक सूची जारी

सीएम ठाकरे समेत मंत्री, नेता डिफॉल्टर लिस्ट में

महाराष्ट्र, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अजित पवार समेत महाराष्ट्र के कई मंत्रियो और नेताओं के बंगले में लाखों का पानी का बिल न भरने की वजह से मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने इन्हें डिफॉलटर घोषित कर दिया है। मुंबई महानगरपालिका की तरफ से पानी के बिल के बकायेदारों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें तमाम मंत्रियों और नेताओं के सरकारी आवास के बिल शामिल हैं, जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया है, साथ ही इन सब बंगलों को डिफाल्टर घोषित किया गया है।

जिन मंत्रियों के सरकारी आवासों के पानी का बिल बकाया हैं, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (वर्षा बंगला), वित्तमंत्री अजित पवार (देवगिरी), जयंत पाटील (सेवासदन), नितीन राउत, उर्जा मंत्री (पर्णकुटी), बाला थोरात, महसूलमंत्री (रॉयलस्टोन), विरोधीपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस (सागर), अशोक चव्हाण (मेघदूत) सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री (पुरातन), दिलीप वलसे पाटील (शिवगिरी), सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे (नंदनवन), राजेश टोपे (जेतवन), नाना पाटोले, विधानसभा अध्यक्ष (चित्रकुट), राजेंद्र शिंगे (सातपुडा), नवाब मलिक (मुक्तागीरी), छगनराव भुजबल (रामटेक), रामराजा निंबालकर विधानभवन सभापति (अजंथा) एवं सह्याद्री अतिथिगृह इत्यादि का नाम शामिल है।

मंत्रियों के आवासों पर लाखों का बिल बकाया

बीएमसी की तरफ से पानी के बकाया दरों की जानकारी जुटाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद की माने तो मुंबई महानगरपालिका आम आदमी के पानी बिल अगर बकाया रहते हैं तो उनके कनेक्शन तुरंत काटने पहुंच जाती है, लेकिन मंत्रियों के आवासों पर लाखों के बिल बकाया हैं, फिर भी उसे सालों वसूलने का काम क्यों नहीं करती। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकारी विभाग समय पर पानी का बिल नहीं भरता है, तो फिर सामान्य जनता पर इसका क्या असर होगा। आम लोग जिनके पानी का बिल बकाया है वो भी लापरवाह हो जाती है जिससे सरकारी राजस्व का ही नुकसान होता है। इस मुद्दे पर मुंबई के मेयर किशोरी पेडणेकर ने कहा है कि साल 2017 में भी बीएमसी ने मंत्रियों के बंगले के बकाया बिलों पर कार्रवाई की थी। हमने उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वह बिल भरें वाटर डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है और हमें उम्मीद है जल्द ही एक साथ तो नहीं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके पानी का बिल मंत्रियों के बंगलों का जमा होगा।

मुंबई हमले की साजिश रचने वाले तहव्वुर राणा की जमानत याचिका खारिज

वाशिंगटन ■ एजेंसी

मुंबई हमले की साजिश के मुख्य किरदार तहव्वुर राणा की जमानत याचिका को एक अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया है। राणा और उसके दोस्त डेविड कोलमैन हेडली ने 26/11 मुंबई हमले की साजिश रची थी, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी। भारत के अनुरोध पर पाकिस्तानी मूल के इस कनाडाई व्यापारी को लॉस एंजिल्स में 10 जून को गिरफ्तार किया गया था।

राणा ने अपनी जमानत याचिका में लॉस एंजिल्स की जिला कोर्ट में कहा कि उसका स्वास्थ्य खराब है, इसके अलावा हिरासत के दौरान ही उसे दो दिल के दौरे पड़ चुके हैं। उसने ये भी तर्क दिया कि वह समाज के लिए खतरा नहीं है। इस दलील का कोर्ट में अमेरिकी सरकार ने विरोध किया। कोर्ट ने राणा को जमानत देने से इंकार कर दिया है। अमेरिकी कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुंबई हमले में उसकी भूमिका सीरियस है उसे जमानत पर खुले में नहीं छोड़ा जा सकता। वह समाज के लिए बराबर खतरा है।

पाक सेना में दस साल किया है काम

तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली दोनों ही साल 2006 से भारत में हमले की तैयारी कर रहे थे, जिसे उन्होंने 26 नवंबर, 2008 के दिन अंजाम दिया था। मूलत: तहव्वुर राणा पाकिस्तान का रहने वाला है, जहां उसने सेना में लगभग दस साल तक चिकित्सकीय सेवाएं दी थीं। पाकिस्तानी-अमेरिकी लश्कर आतंकवादी डेविड हेडली अपने गुनाह को कबूलते हुए सरकारी गवाह बन गया था। फिलहाल वह भारत में किए गए हमले में अपनी भूमिका के लिए एक अमेरिकी जेल में 35 साल की सजा काट रहा है।

अमेरिका ने मानी भारत की मांग

इसी बीच अमेरिकी सरकार ने भारत की इस मांग का समर्थन भी किया कि राणा के प्रत्यर्पण के संबंध में दिए गए डाक्यूमेंट्स को सार्वजनिक न किया जाए। भारत द्वारा प्रत्यर्पण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में मुंबई आतंकवादी हमले में राणा की भागीदारी के बारे में जानकारी शामिल है, जो राणा के साथ साझा की जाएगी।

सऊदी अरब के जेद्दा तट पर विस्फोट

मॉस्को, (एजेंसी)। सऊदी अरब के बंदरगाह शहर जेद्दाह में विस्फोट के दौरान तेल टैंकर के चालक दल का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ। कंपनी ने कहा कि मास्टर ने तुरंत सभी डिस्चार्ज संचालन को बंद कर दिए और जहाज पर आपातकालीन प्रक्रियाओं को चालू कर दिया। चालक दल ने आग को बुझा दिया है। सभी 22 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

बिहार: नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात से बन रहे हैं साथ आने के आसार

पटना, (एजेंसी)। क्रिकेट की पिच और राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, जैसे क्रिकेट में लास्ट बॉल पर आकलन करना मुश्किल है, वैसे हीं राजनीति में कब कौन किसके खेमे में चला जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं रहता। हाल के दिनों में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरएलएसपी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के मुलाकात ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि सियासत में कुछ भी संभव है, हालांकि जेडीयू के साथ आरएलएसपी के विलय की बात उपेंद्र कुशवाहा पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन आरएलएसपी सूत्रों का दावा है कि एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के साथ आरएलएसपी के सम्मानजनक एलायंस पर चर्चा जरूर हो रही है।

आरएलएसपी की विश्वस्त सूत्रों की मानें तो उपेंद्र कुशवाहा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसी भी कीमत पर निराश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कुशवाहा का मानना है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती से खड़ा करने में सब ने पूरी मेहनत की है, इसलिए एनडीए में आरएलएसपी के सम्मान जनक वापसी की उम्मीद की जा सकती है। इस विषय पर हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से इस बात पर चर्चा भी की है।

जेडीयू चाहती है कि राजग का हिस्सा बनें कुशवाहा

बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ जिस तरह भूमिका निभाई है, उससे नाराज जेडीयू भी यही चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा राजग का हिस्सा बने। इससे जेडीयू को भी प्रदेश की सियासत में लव-कुश समीकरण समेत पिछड़े वर्ग की राजनीति को मजबूत कर उसे साधने में मदद मिलेगी, क्योंकि जेडीयू के पास उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर कुशवाहा बिरादरी का कोई भी बड़ा नेता नहीं है।

क्या एनडीए से बाहर होगी एलजेपी?

बात करें अगर केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की तो विस्तार के क्रम में यदि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान को जगह नहीं मिलती है तो माना जाएगा कि जेडीयू के दबाव में एलजेपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी, हालांकि अभी तक ऐसी कोई सियासी हलचल नहीं है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जेडीयू ने साफ संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा चुनाव में एलजेपी की भूमिका को भाजपा को देखना चाहिए और और उस पर एक्शन लेना चाहिए। बताते चलें कि चुनाव में जेडीयू की जो सीटें कम हुई उसके लिए एलजेपी को ही जिम्मेदार माना जा रहा है।

भारतीय जवानों ने चीनी सेना का किया डटकर सामना : राजनाथ

पीएलए को वापस जाने के लिए किया मजबूर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत-चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारतीय सशस्त्र बलों ने चीनी सेना का 'पूरी बहादूरी' के साथ सामना किया और उन्हें वापस जाने को मजबूर किया।

उद्योग चैंबर 'फिक्की' की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि हिमालय की हमारी सीमाओं पर बिना किसी उकसावे के अक्रामकता दिखाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है, मौजूदा समझौतों को कैसे चुनौती दी जा रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने पीएलए (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) का पूरी बहादूरी से सामना किया और उन्हें वापस जाने को मजबूर किया। हमारे बल ने इस साल जो हासिल किया, उस पर देश की आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने फिर की मोदी सरकार की तारीफ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने एक बार फिर मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने फिक्की के 93वें सालाना सम्मेलन में कहा कि कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी, लेकिन पीपीई किट, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों को बनाने की हमारी क्षमता बढ़ी। इसके लिए शर्मा ने मोदी सरकार को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना से संकुचित हुई है, लेकिन पीपीई किट, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों के निर्माण के मामले में हमारी क्षमता बढ़ी है, जिसका श्रेय लोगों को समाज को और सरकार को जाता है। इससे पहले आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला के दौरे की भी तारीफ की थी। उन्होंने पीएम के इस कदम को वैज्ञानिकों के कोरोना वायरस वैक्सीन उत्पादन करने के काम को पहचान देने वाला बताया था। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह कोरोना से प्रभावित हुए तबकों को आर्थिक मदद देने में अधिक उदार रुख दिखाए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था करे। उनके अनुसार, देश को जीडीपी के 10 फीसदी का नुकसान हुआ है और 2019-20 की स्थिति तक आने में उसे एक साल का समय और लगेगा।

आज के दौर कि बेटियां हमारा फ्यूचर हैं : करणवीर शर्मा

मुबई, (ब्यूरो)। स्टार प्लस पर जल्द ही चर्चित प्रोड्यूसर दिया और टोनी सिंह एक नया फिक्शन शो शौर्य व अनोखी की कहानी पेश करने जा रहे हैं। यह शो एक साधारण लड़की की कहानी पर केंद्रित है, जो पुरुष प्रधान समाज और रूढ़िवादी सोच के चलते उस पर आने वाली कई चुनौतियों का सामना करती है। पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित इस शो में करणवीर शर्मा (शौर्य सभरवाल) और देबतमा साहा (अनोखी भल्ला) मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। शो के जरिए करणवीर टेलीविजन पर फिर वापसी करते नजर आएंगे।

शो के संबंध में अभिनेता करणवीर शर्मा ने कहा कि यह शो दो विचारधाराओं को लेकर बना है, जो नई और पुरानी सोच के द्वंद को बयां करती है। शो का बैकड्रॉप यही है कि कैसे जब दो अलग सोच वाले लोग मिलते हैं तो कैसे यह कहानी आगे बढ़ती है। इसके अंदर जब हम थोड़ा, रोमांस और सस्पेंस डालेंगे तो कहानी और भी निखरकर आएगी। यह कहानी इस सोच को बयां करेगी कि आज के दौर कि बेटिया हमारा फ्यूचर हैं और वह किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस शो में काम करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत वक्त से मैंने एक रोमेंटिक रोल में खुद को नहीं देखा था। एक रोमेंटिक हीरो जैसा किरदार मैंने बहुत सालों से नहीं किया था, जिसे मुझे एक्सप्लोर करना था और वह मुझे शो के किरदार के जरिए करने को मिल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं यह शो स्टार प्लस पर प्रसारित होगा, जिनके साथ मैं बहुत पहले से जुड़ना चाह रहा था इसलिए इन सभी को देखते हुए मैं बहुत खुश हूं।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे!
कोरोना वायरस से
सावधान रहे
क्योंकि सावधानी
ही बचाव हैं।
कोरोना को धोना हैं।

39 सालों से न्याय की आस लगाए दुनिया छोड़ गए बेहमई कांड के वादी राजाराम सिंह

लखनऊ, (एजेंसी)। 14 फरवरी 1981 का मंजर देखने वाले कानपुर देहात के बेहमई के राजाराम सिंह भी न्याय की आस लिए दुनिया छोड़ गए। फूलन गैंग ने उनके छह भाइयों और भतीजों के साथ गांव के 20 लोगों को गोलियों से भून दिया था। जब सारा गांव कांप रहा था, राजाराम मुकदमा लिखाने के लिए आगे आए थे, उन्होंने फूलन देवी और मुस्तकीम समेत 14 को नामजद कराते हुए 36 डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पूरे देश को दहला देने वाला बेहमई कांड लचर पैरवी और कानूनी दांव पेंच में ऐसा उलझा कि 39 सालों में भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। देश के इस बहुचर्चित मुकदमे में नामजद अधिकांश डकैतों के साथ ही 28 गवाहों की मौत हो चुकी है। आरोपित मानसिंह, विश्वनाथ व रामकेश मुकदमे में 39 साल से फरार चल रहे हैं। कुर्की के साथ ही इनके स्थाई वारंट जारी किए गए और फिर मुकदमे से इनकी पत्रावली अलग कर बाकी बचे आरोपितों के खिलाफ सुनवाई पूरी की गई। इनमें डकैत पोसा, भीखा, विश्वनाथ श्याम बाबू ही बचे हैं, जिनके खिलाफ फैसले का इंतजार है।

आशंका राजस्थान कांग्रेस में फिर से सियासी घमासान की सुगबुगाहट

आलाकमान के निर्देश पर अजय माकन करेंगे दौरा

जयपुर, (एजेंसी)। राजस्थान कांग्रेस में फिर से सियासी घमासान की सुगबुगाहट के बीच प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजस्थान दौरे पर आएंगे। माकन का यह दौरा सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले होने की संभावना है। दरअसल राजस्थान सहित अन्य राज्यों में एक के बाद एक मिल रही हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सभी प्रभारियों को अपने प्रदेश में अधिक दौरे करने के निर्देश दिए हैं।

अजय माकन का यह दौरा इस मायने में अहम है कि इसके बाद राजस्थान में संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रदेश में 20 दिसंबर तक आचार संहिता है, इसलिए राजनीतिक नियुक्तियों का काम इसके बाद ही होगा। इन नियुक्तियों में सीएम अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट कैंप दोनों को माकन किस तरह साध पाएंगे, इस पर सबकी नजर होगी।

पायलट खेमे को नजरअंदाज नहीं करेगा आलाकमान

मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में इशारों-इशारों में पायलट खेमे पर जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए उससे यह स्पष्ट हैं कि संगठन एवं राजनीतिक नियुक्तियों में वे पायलट खेमे को तरजीह देने को कतई तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर माकन ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस आलाकमान पायलट खेमे को नजरअंदाज नहीं करेगा। माकन पहले ही कह चुके हैं कि दिसंबर और जनवरी के बीच राजस्थान कांग्रेस में संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

माकन को करना पड़ सकता है कई सवालों का सामना

निकाय और पंचायत चुनावों में कांग्रेस के मंत्रियों और कई विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा है और इसकी जिम्मेदारी से माकन भी नहीं बच सकते। यह सवाल उठेगा कि जब चुनावों से पहले टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में असंतोष पनप रहा था और यह बात सामने आई थी कि मंत्री-विधायक अपने रिश्तेदारों को ही टिकट बांट रहे हैं, तब संगठन की तरफ से इसमें दखल क्यों नहीं दिया गया? एक वरिष्ठ विधायक का कहना है कि हार के बाद इन मंत्रियों और विधायकों की जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई? ऐसे कई सवाल हैं जो राजस्थान दौरे में अजय माकन का इंतजार कर रहे होंगे।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की सरप्रस्ती अधीन राज्य स्तरीय एडज दिवस समारोह आयोजित

पंजाब में हालात ठीक, परन्तु लोगों को सचेत रहने की जरूरत - कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू

■ चंडीगढ़/लुधियाना/ब्यूरो

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू की सरप्रस्ती अधीन विश्व एडज दिवस मनाने के लिए रा%य स्तरीय समागम आयोजित किया गया। पंजाब में एडज की स्थिति को देखने के लिए विशेष तौर काम कर रही पंजाब स्टेट एडज कंट्रोल सुसाइटी ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लुधियाना के सहयोग से यह समागम लुधियाना में करवाया। विश्व एडज दिवस हर साल विश्व -व्यापक मनाया जाता है जिससे अब तक इस की रोकथाम के लिए किये प्रयासों और इस बीमारी के ओर फैलने से रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों की समीक्षा की जा सके। पंजाब राज्य में पंजाब स्टेट एडज कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से यह दिन जागरूकता पैदा करने, इस बीमारी संबंधी समझ, जानकारी और तजुर्बों का आदान-प्रदान करने के लिए मनाया जाता है, जिससे एच.आई.वी. और एडज से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन जाहिर होता है। इस साल विश्व एडज दिवस विश्व स्तरीय एकता, सांझी जिम्मेदारी के विषय से मनाया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में एडज के पहले केस का पता लगने से अब 39 सालों से अधिक समय हो गया है। उस समय, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह संक्रमण असाधारण गुंजाईशों और बेमिसाल रुकावटों की एक विश्वव्यापी समस्या बन जायेगी। एक दशक पहले भी, एचआईवी और एडज मुख्य तौर पर एक गंभीर संकट के तौर एवं माने जाते थे। आज यह स्पष्ट है कि एडज एक विकास की मुसीबत बन गई है और अब यह दर्शाने वाले सबूत हैं कि अगर रुझान नहीं रोका गया, तो अब तक के विकास के प्राप्त किये लाभों को खत्म कर देगा।

उन्होंने आगे कहा कि देश के बाकी हिस्से के मुकाबले पंजाब में हालात काफी हद तक ठीक हैं, क्योंकि यहाँ अधिकतर सुरक्षित है।

इस मौके पर श्री अमित कुमार विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पंजाब-कम-प्रोजैक्ट डायरैक्टर पंजाब स्टेट एडज कंट्रोल सोसाइटी ने कहा कि पंजाब राज्य में नशा और नशे से सम्बन्धित एच.आई.वी. की बढ़ रही घटनाएं बहुत चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या गंभीर है क्योंकि नौजवानों की बढ़ रही संख्या, नशे की खासकर इंजेक्शन के द्वारा दवाओं के प्रयोग की आदत में आ रही है। यह देखा गया है कि पिछले 4-5 सालों के समय के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करने का ढंग बदल गया है और नशा करने वाले जुबानी गोली से टीके लगाने के ढंग अपना रहे हैं। इसके नतीजे के तौर पर राज्य में नशे का प्रयोग और सम्बन्धित एच.आई.वी. के टीके लगाने की घटनाओं में विस्तार हुआ है। इस समय राज्य के 18 जिलों में 35 ओपीओड सबस्टिट्यूशन थैरेपी (ओ.एस.टी.) केंद्र काम कर रहे हैं। इसने आई.डी.यूज. को उनके टीके लगाने की आदत एवं काबू पाने में सहायता की है। आई.डी.यू. जो नियमित तौर पर इलाज करवा रहे हैं वह स्थिर होने के संकेत दिखा रहे हैं। पंजाब का स्वास्थ्य विभाग और सोसायटी नशाखोरी के मुद्दों को हल करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है जिससे नशे के प्रयोग के टीके पर खास ध्यान दिया जा सके और इसको रोका जा सके।

सिवल सर्जन डा. राजेश कुमार बग्गा ने कहा कि माँ से बच्चों के संचारण भी रोका जा सकता है, इसके लिए हमें गर्भवती महिलाओं को एच.आई.वी. टेस्टिंग यकीनी बनाना चाहिए और माँ से बच्चे तक संचार को खत्म करने के लिए एंटी -रीटरोवायरल इलाज करवाना चाहिए। और अधिक जानकारी देते हुये मनप्रीत छतवाल असिस्टेंट प्रोजैक्ट डायरैक्टर ने बताया कि 915 इंटीग्रेटड काउंसलिंग और टेस्टिंग सैंटर (आई.सी.टी.सी.) सभी मैडीकल कालेजों, जिलों के अस्पतालों और सब डिविजनल अस्पतालों/सीएचसी/पी.एच.सी.एस, और केंद्रीय जेलों में चल रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ के द्वारा लोगों को उनकी अपनी मर्जी एवं या डाक्टरी प्रदाता के द्वारा दी सलाह के अनुसार मुफ्त एच.आई.वी. की सलाह और जांच सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पंजाब में, जिलों/उप-जिलों के अस्पतालों और सरकारी मैडीकल कालेजों में 31 एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लिीनिकें (डी. एस. आर.सी.) स्थापित हैं।

विश्व एडज दिवस के मौके पर लोगों को संबोधन करते हुये स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा, 'आओ हम सभी इन बातों को अमल में लाने का वायदा करें, आओ संकल्प करें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पंजाब को एडज मुक्त बनाने के लिए हमेशा यत्नशील रहेंगे।

SPORTS PLANET स्पोर्ट्स प्लैनट

आईसीसी रैंकिंग में केन विलियमसन से आगे निकले विराट कोहली, जानिए बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में कौन ?

■ दुबई/ब्यूरो

भारतीय कप्तान विराट कोहली मंगलवार को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गये जबकि चेतेश्वर पुजारा सातवें और अजिंक्य रहाणे दसवें स्थान पर हैं। कोहली 886 रेटिंग अंकों के साथ भारतीय बल्लेबाजों में शीर्ष पर हैं लेकिन वह आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (911 अंक) से पीछे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन तीसरे स्थान पर खिसक गये हैं। उनके बाद आस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन, पाकिस्तान के बाबर आजम और चोटिल डेविड वार्नर का नंबर आता है। पुजारा 766 अंक के साथ इस सूची में सातवें स्थान पर हैं। उनके बाद बेन स्टोक्स (760), जो रूट (738) और भारतीय टेस्ट उप कप्तान रहाणे (726) शीर्ष दस में शामिल बल्लेबाज हैं।

भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह (779 अंक) और अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (756) गेंदबाजी रैंकिंग में क्रमश: आठवें और दसवें स्थान पर है। इस सूची में आस्ट्रेलिया के पैट कमिन्स (904) शीर्ष पर हैं। उनके बाद इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड और न्यूजीलैंड के नील वैगनर का नंबर आता है। भारत के दो खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और अश्विन आलराउंडरों की सूची में शीर्ष दस में शामिल हैं। स्टोक्स इस सूची में शीर्ष पर हैं।

जडेजा 397 रेटिंग अंकों के साथ वेस्टइंडीज के जैसन होल्डर के बाद तीसरे स्थान पर है जबकि अश्विन के 281 अंक हैं और वह छठे स्थान पर हैं। टीमों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत अभी तीसरे स्थान पर है क्योंकि न्यूजीलैंड हाल में वेस्टइंडीज पर 2-0 की जीत से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

भारत के 114 अंक हैं और वह न्यूजीलैंड और तालिका में शीर्ष पर काबिज आस्ट्रेलिया से दो अंक पीछे है। आस्ट्रेलिया दशमलव में गणना करने के बाद न्यूजीलैंड से आगे है। इंग्लैंड चौथे स्थान पर है। उसके बाद श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का नंबर आता है। भारत के पास हालांकि आस्ट्रेलिया के खिलाफ एडीलेड में गुरुवार से शुरू होने वाली चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला के जरिये आगे बढ़ने का मौका रहेगा।

स्टोक्स इस सूची में शीर्ष पर हैं। जडेजा 397 रेटिंग अंकों के साथ वेस्टइंडीज के जैसन होल्डर के बाद तीसरे स्थान पर है जबकि अश्विन के 281 अंक हैं और वह छठे स्थान पर हैं।

पंजाब पुलिस ने सरहद पार से ड्रोन के द्वारा नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल के दो सदस्यों को किया काबू

पाकिस्तान और अन्य देशों के बीच के नैटवर्क की जांच, खालिस्तानी संबंधों का हुआ खुलासा

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब पुलिस की तरफ से खालिस्तानी सरगर्मियों से सम्बन्धित पाकिस्तान आधारित तस्करों समेत अंतरराष्ट्रीय नैटवर्क के द्वारा सरहद पार से ड्रोन के द्वारा नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी करने वाले एक मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

मुलजिमों की पहचान लखबीर सिंह उर्फ लक्खा और बचित्तर सिंह के तौर पर हुई है जिनको अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस ने विशेष सूचना के द्वारा गिरफ्तार किया है। मुलजिमों से अगली जांच की जा रही है जिससे अमृतसर जेल में बंद चार नशा तस्करों समेत उनके साथियों का पता लगाया जा सकेगा।

डीजीपी दिनकर गुप्ता ने यह जानकारी देते हुये बताया कि मुलजिमों से एक फूल स्पोर्टर स्टैंड वाला एक कुआडकौपटर ड्रोन और एक स्काईडरोइड टी 10 2.4 जीएचजैड 10सीएच एफ. एच.एस. एस ट्रांस्मिटर, मिनी रिसीवर और कैमरा के साथ एक .32 बोर की रिवाल्वर और एक स्कॉरपीयो कार नंबर एचआर -35 एम 3709 और कुछ जिंदा कारतूस और नशीले पदार्थ बरामद किये गए हैं।

इस केस सम्बन्धी जानकारी देते हुये डीजीपी ने बताया कि मुख्य शक्की लखबीर सिंह निवासी गाँव चक्क मिशरी खान, थाना लोपोके को सोमवार को गुरुद्वारा टाहला साहब, थाना चट्टीविंड, अमृतसर (ग्रामीण) के पास से काबू किया गया। जांच के दौरान लखबीर सिंह ने खुलासा किया कि उसने लगभग चार महीने पहले एक कुआडकाप्टर ड्रोन दिल्ली से खरीदा था और फिलहाल यह ड्रोन उसके साथी बचित्तर सिंह के घर गुरू अमरदास ऐवीन्यू, अमृतसर में था।

एसएसपी ध्रुव धईआ की निगरानी अधीन एएसपी राणा और डीएसपी नागरा के नेतृत्व अधीन हुई जांच से पता लगा है कि लखबीर सिंह अजनाला के 4 बड़े नशा तस्करों के साथ नजदीकी और बार-बार संपर्क करता था, जो इस समय अमृतसर जेल में बंद हैं। जेल में तलाशी लेने से लखबीर के साथी नशा तस्कर सुरजीत मसीह के पास से एक टच स्मार्टफोन बरामद हुआ।

डीजीपी के अनुसार, अब तक की जाँच से पता लगा है कि लखबीर सिंह ने विदेशी तस्करों और इकाईयों के साथ एक विशाल संचार नैटवर्क स्थापित किया था और वह पाकिस्तान के एक नामी तस्कर चिशती के साथ अक्सर संपर्क में रहा था। चिशती पाकिस्तान आधारित खालिस्तानी संचालकों के साथ भी संपर्क में है और पिछले समय के दौरान पाकिस्तान से भारत में सरहद पार की महत्वपूर्ण खेपों की तस्करी करता रहा है।

मौजूदा समय अमृतसर जेल में कैद सिमरनजीत सिंह ने लखबीर सिंह को सरहद पार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए एक ड्रोन खरीदने के लिए कहा था। श्री गुप्ता ने बताया कि सिमरनजीत सिंह को भी इस केस में मुलजिम नामजद किया गया है। लगभग चार महीने पहले, लखबीर सिंह और उसके साथी गुरपिन्दर सिंह नयी दिल्ली गए और उन्होंने टीआरडी ऐंटरप्राइजज, जनकपुरी से 4 लाख रुपए में स्काईडरायड टी 10 2.4 जी.एच.जैड 10 सीएच एफएचएसएस ट्रांसमिटर के साथ हैवी ड्यूटी कुआडकाप्टर ड्रोन खरीदा था।

स्पोर्टर स्टैंड और स्काईडरायड टी 10 2.4 जीएचजैड 10सीएच एफएचएसएस ट्रांसमिटर के साथ मिनी रिसीवर और कैमरे वाला बरामद किया ड्रोन।

इस सम्बन्धी लखबीर सिंह और बचित्तर सिंह दोनों निवासी चक्क मिशरी खान, थाना लोपोके और गुरपिन्दर सिंह खापड़ खेड़ी, थाना घरिंडा और अनजान व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नं. 202 तारीख 14.12.2020 को आइपीसी की धारा 411, 414, आर्मज़ एक्ट की धारा 25, एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 23 और एयरक्राफट एक्ट, 1954 की धारा 10, 11, 12, के अंतर्गत थाना घरिंडा में दर्ज किया गया है।

बलबीर सिद्धू ने मिशन फतेह के अंतर्गत कोरोना वायरस सम्बन्धी 4 एल.ई.डी. जागरूकता वैनों को हरी झंडी दी

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पंजाब स. बलबीर सिंह सिद्धू की तरफ से आज मिशन फतेह के अंतर्गत कोरोना वायरस सम्बन्धी 4 एल.ई.डी. जागरूकता वैनों को हरी झंडी दी गई। इस मौके पर बातचीत करते हुये स. बलबीर सिद्धू ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के मिशन फतेह के अंतर्गत यह 4 जागरूकता वैनें अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) के जोखिम वाले शहरी/अर्ध शहरी इलाकों में जाकर लोगों को कोरोना वायरस, इसके लक्षण और रोकथाम आदि के बारे बड़ी स्करीन पर फिल्में दिखा कर इस महामारी संबंधी जागरूक करेंगी। कोरोना के खात्मे के लिए बनाई गई वैक्सीन के बारे जानकारी देते हुये स. सिद्धू ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण मुहिम के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और भारत सरकार की तरफ से सप्लाई मिलते ही दिशा-निर्देशों के अनुसार टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जायेगा । स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लोगों को कोरोना वायरस से बचाव रखने के लिए मास्क पहनने, हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाऐ रखने जैसी सावधानियों की पालना करने की अपील की गई। इस मौके पर डायरैक्टर हैल्थ सर्विसेस डा. मनजीत सिंह, स्टेट नोडल अफसर -कोविड -19 डा. राजेश भास्कर, स्टेट प्रोग्राम अफसर और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेटकीपर के तौर पर साहा की जगह उतरे पंत : सुनील गावस्कर

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि भारतीय टीम प्रबंधन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरूवार से शुरू हो रही चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में विकेटकीपर के तौर पर रिधिमान साहा की जगह आक्रामक ऋषभ पंत को उतारना चाहिये। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 10000 रन पूरे करने वाले गावस्कर ने कहा कि पहले टेस्ट में पंत भारतीय बल्लेबाजी क्रम को लचीलापन देगा। पंत ने गुलाबी गेंद से खेले गए दूसरे अभ्यास मैच में 73 गेंद में 103 रन बनाये थे। गावस्कर ने कहा ,'' चयन समिति के लिये यह काफी कठिन होगा क्योंकि ऋषभ ने चार साल पहले चारों टेस्ट खेले थे। उसने एक शतक भी बनाया था और विकेट के पीछे भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। कुछ दिन पहले ही उसने शतक जमाया है तो वह प्रबंधन की पसंद होना चाहिये।'' उन्होंने कहा कि विकेटकीपिंग में तकनीकी तौर पर अधिक सक्षम साहा की बजाय वह पंत को तरजीह देंगे क्योंकि आस्ट्रेलियाई पिचें विकेटकीपिंग के लिये चुनौतीपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''जिन पिचों पर गेंद टर्न लेती है , वहां सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर की जरूरत होती है और ऐसे में साहा पहली पसंद होते। लेकिन यहां विकेटकीपर स्टम्प के थोड़ा पीछे रह सकता है और उसके पास अधिक समय होगा तो ऋषभ सही पसंद होंगे।''

गावस्कर और एलेन बॉर्डर दोनों ने पारी की शुरूआत के लिये मयंक अग्रवाल के साथ पृथ्वी साव की बजाय शुभमन गिल को उतारने पर जोर दिया। गावस्कर ने कहा ,'' भारतीय शीर्षक्रम अभी अस्थिर है। मयंक अग्रवाल एक सलामी बल्लेबाज है लेकिन उसके साथ कौन उतरेगा। शुभमन गिल या पृथ्वी साव।'' गिल ने दो अभ्यास मैचों में 0, 29, 43 और 65 रन बनाये जबकि साव का स्कोर 0 , 19 , 40 और तीन रन रहा। बॉर्डर ने कहा ,'' मैंने सिडनी में गिल की बल्लेबाजी देखी और मैं काफी प्रभावित हूं।

उसकी तकनीक अच्छी है और उम्र में कम होने के कारण कुछ शॉट्स अपरिपक्व हैं लेकिन वह उम्दा बल्लेबाज है। मैं उसे ही चुनूंगा।'' गावस्कर ने कहा ,'' साव को अभी अपनी बल्लेबाजी पर कुछ काम और करना होगा। सलामी बल्लेबाज को समय की जरूरत होती है ताकि नयी गेंद को बखूबी खेल सके। उसे अपना डिफेंस मजबूत करना होगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि मयंक अग्रवाल से उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है।

बलबीर सिंह सिद्धू सिवल अस्पतालों में जख्मी किसानों को मिले

किसान दीप सिंह गाँव पोपना जिला मोहाली और सुखदेव सिंह गाँव डडिआना जिला फतेहगढ़ साहिब की हुई दुर्घटना में मौत

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

स्वास्थ्य एवं श्रम मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सिवल अस्पताल मोहाली में एक दुर्घटना में जख्मी हुए किसानों का हालचाल पूछा। यह किसान दिल्ली मोर्चे से वापस आ रहे थे जो मोहाली जिले के गाँव मजातड़ी और रंगीयां के निवासी हैं।

इस संबंधी और जानकारी देते हुये स. बलबीर सिद्धू ने बताया कि यह किसान छोटा हाथी (चार पहिया वाहन) में सवार थे और भागोमाजरा मोहाली में टिप्पर से हुई टक्कर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण दो किसान दीप सिंह गाँव पोपना जिला मोहाली और सुखदेव सिंह गाँव डडिआना जिला फतेहगढ़ साहिब की मौत हो गई जबकि 4 किसानों की हालत नाजुक होने के कारण इनको सिवल अस्पताल मोहाली से आगे पी.जी.आई और 32-अस्पताल, चण्डीगढ़ रैफर कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि 3 किसान मोहाली अस्पताल में उपचाराधीन हैं जिनका अस्पताल जाकर हालचाल पूछा। उन्होंने बताया कि 2 किसानों को छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने एस.एम.ओ डा. अरीत कौर को किसानों के मानक इलाज यकीनी करने के लिए हिदायतें भी दीं।

निकाय विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने रीजन के शहरों की काउंसिल व पंचायतों के कामकाज की समीक्षा की

इस सरकार की तरफ से लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा

■ जालंधर/ब्यूरो

स्थानीय निकाय विभाग के डिप्टी डायरेक्टर दरबार सिंह की अगवाई में मंगलवार को स्थानीय सर्किट हाउस में जालंधर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों की नगर काउंसिलों की एक बैठक की गई जिसमें संबंधित काउंसिल के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश सरकार की तरफ से शहरों के चौतरफा विकास के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि नगर कौंसिल व पंचायतों की स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों में बदलने का काम चल रहा है जो कि चार नगर काऊंसिल में पूरा हो चुका है। बाकी नगर कौंसिल व पंचायतों को भी यह प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने के लिए निर्देश दिए। डिप्टी डायरेक्टर ने आगे बताया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी करने का प्रोजेक्ट भी सिर्फ जालंधर रीजन में ही चल रहा है जिसके तहत 16 शहरों में 5902 आवारा कुत्तों की नसबंदी करके यह काम खत्म किया जा चुका है जबकि नकोदर और अलावलपुर में काम चल रहा है।

उन्होंने नसबंदी का प्रोजेक्ट चला रही कंपनी को बाकी के शहरों में भी काम जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। रेहडी संचालकों को सस्ते कर्ज मुहैया करवाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से चलाएगी इस योजना के तहत बड़ी तादाद में स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ देने की लिए कदम उठाए गए हैं और उनकी अर्जियां ऑनलाइन की जा रही हैं। जिन शहरों में अर्जीयां ऑनलाइन नहीं हुई उन्हें 3 दिन का समय दिया गया ताकि वह भी स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन ऑनलाइन कर सकें। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत रीजन में आने वाले 30 शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है और बाकी शहरों में भी इस मुहिम के तहत काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि पंजाब शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम फेस वन के तहत जो काम लंबित है उन्हें जल्द मुकम्मल करने और फेस 2 के कार्यों को 31 दिसंबर 2020 से पहले शुरू करके रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्डिंग फीस, वाटर सप्लाई व सीवरेज के बिलों, किराए इत्यादि की रिकवरी की समीक्षा भी की गई।

शिक्षा मंत्री के निर्देशों पर 45 स्कूलों के जिमनेजियम परिसरों की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब सरकार ने स्कूलों में खेल बुनियादी ढांचे का स्तर सुधरने के लिए राज्य के 45 स्कूलों के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है जिससे स्कूलों में नये उभर रहे खिलाड़ी बढ़िया तरीके से अपनी प्रेक्टिस जारी रख सकें। इसकी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा मंत्री श्री विजय इंद्र सिंगला के निर्देशों के बाद 10 जिलों के 45 स्कूलों के जिमनेजियम परिसरों की मुरम्मत के लिए 2,64,50,113 रुपए जारी किये गए हैं।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.